

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... बनाम

किस्म मुकदमा अफलातून मु. नं० शीकत 60 वर्ष 2018

दिनांक

19-6-18

आज्ञा पत्र


अपील द्वाे राजस्व से अफलातून का बिन्दू रिजर्व रहेगा। स्थान पर पत्र पर अपीलान्ट को सुना गया। वकील अपीलान्ट ने इस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि आराजी समेत 214, 320 कुल कित्ता-2 रकबा 5.49 हेक्टर गाम मण्डेला में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा, रेस्पोंडेन्ट नं०-1 का 1/4 हिस्सा एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 में 7 बीघर स्थित ल्प से 1/4 हिस्सा है। जिलाधीनरी के निर्णय का अन्त करते है। आराजी का विधित बंटवारा नहीं हुआ है। बिना बंटवारा ही अन्त से एक संस्थातेदार का अन्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर बिना बन्त संस्थातेदार का अन्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जिसे अपीलान्ट अपने हिस्से की आराजी का न तो विकास कर सकता और न ही सिंचाई के लिये बिजली का कनेक्शन ले सकता है। अतः अदालत मातहत के निर्णय की क्रियान्विति को स्थगित किया जावे।

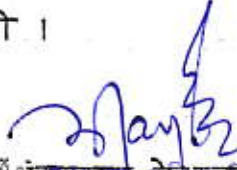


सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

बहस बगैर समाहत की गई । प्रार्थना पत्र एवं अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत ने अन्तरिम आदेश जारी कर उक्त विवादित आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं करने, अकृषि योग्य नहीं बनाये तथा रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये हैं । अदालत मातहत का यह आदेश प्रार्थी/रिस्पोंडेंट को एकपक्षीय तुरन्त अन्तरिम आदेश पारित किया है । अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र धारा-212 राज0 काश्तकारी अधिनियम का विचारा-धीन है। अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र धारा-212


कृपकन्ध अधिकारी एवं
परवेज रावत अमील अधिकारी
सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	<p>राज्य कार्यकारी अधिनियम का निर्णय अन्तिम रूप से नहीं किया है। हम यहाँ पर यह उचित मानते हैं कि अदालत मातहत के अन्तरिम आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न कर अपील को इसी स्तर पर अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं।</p> <p>अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इसी निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र धारा-212 राजस्थान कार्यकारी अधिनियम का उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये 30 दिन में अन्तिम रूप से निर्णय पारित करें। पक्षकार अदालत मातहत में नियत दिनांक को उपस्थित हों। पत्रावली बाद तुरन्त तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  शंकरप्रसाद ओझा भू-प्रबंधन कार्यकारी अधिकारी पदेन राजस्व अधीन प्राधिकारी सीकर </p>	